established by Government in various parts of the country in the interest of child labour working in the factories/ industries, private organisations; and

(b) what is the amount allocated to these centres during the current financial year and what are the details of their activities?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) As a part of the National Child Labour Policy, 1987, the government has been implementing National Child Labour Projects (NCLP) in areas of high concentration of child labour. These projects are implemented generally through NGOs and voluntary organisations under the overall supervision of the project society at the district level. A major activity undertaken under. the NCLP is establishment of special schools to provide basic needs like non-formal education, vocational training, supplementary nutrition etc. to the children withdrawn from employments. During the current year, 63 National Child Labour Projects have been approved and initial assistance amounting to Rs. 5.24 crores has been released. This is in addition to 12 ongoing National Child Labour Projects. In all around 1,36,000 children are covered through more than 2200 special schools in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat,-Orissa, West Bengal, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu.

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का दुरूपयोग किये जाने संबंधी मामले

1422. **श्री सुंदर सिंह भंडारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के वर्ष 1992 में प्रारम्भ किये जाने से लेकर अब तक निजी और सरकारी क्षेत्रों में इसका दुरूपयोग किए जाने के मामलों की संख्या क्या है और इसके कारण कितने वर्ष-वार और क्षेत्र-वार आंकड़े हैं,

(ख) कितने लाइसेंस रद्द किये गये हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग)इस दुरूपयोग को रोकने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वी.ए.बी.ए.एल.के कथित दुरूपयोग के 580 मामले उनकी जानकारी में आए है । चूंकि वी.ए.बी.ए.एल.(वाबाल) योजना में निर्यात शुल्क से छूट देने पर विचार नहीं किया गया है इसलिए इस कारण से किसी प्रकार की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ख) इनमें से अनेक मामलों की या तो जांच चल रही है या ये निर्णयाधीन है । निर्णय की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद अब कुल मिलाकर 27 मूल्यवर्धित अग्रिम लाइसेंसों को रद्द किया गया है ।

(ग) इस योजना को चलाने के लिए इस वर्ष विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है । जिन्हें इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए वृहत रूप से प्रभावी होना माना गया है । इसके अलावा, शुल्क छूट योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों के संबंध में 1.4.1995 से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया गया है जिससे कि इस योजना के अंतर्गत निर्यात से पहले मोडवेट का अभिशून्यन नहीं होने की समस्याओं पर विचार किया जा सके ।

Construction of Hospitals for working class

1423. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to construct a network of hospitals for the working class all over the country;

(b) if so, details of this proposal;

(c) is it a fact that workers suffering from occupational diseases are not getting any attention; and

(d) steps proposed to help workers suffering from occupational diseases?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) There are 122 ESI hospitals